जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 180 प्रभात कोटा, मंगलवार 15 अप्रैल, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

## अजीब सी शान्ति है, भारत के टॉप अरबपतियों में

### दशकों की मेहनत व भाग्य से निर्मित उनके साम्राज्य तिलमिला गये, ट्रम्प के टैरिफ वॉर से उभरी अस्थिरता से

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। यह साल गायब होते अरबपतियों का रहा है। दशकों की मेहनत से बनाई गई संपत्तियाँ कुछ ही महीनों में धराशायी हो गई हैं। भारत के अभिजात्य वर्ग के बिज़नैस गलियारे, जो एक समय पर वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से भरे थे, तथा जहाँ बिज़नैस एक्सपैन्शन की बातें होती थीं, वहाँ अब खोई हुई संपत्ति की बेचैन खामोशी गूँज रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक परिस्थितियाँ बिगड़ीं और बाज़ार अनिश्चितता के बोझ के नीचे दब गए, तो भारत के सबसे अमीर लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसकी उन्हें न तो उम्मीद थी और न ही जिससे वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इन्डैक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सन् 2025 के पहले कुछ महीनों में ही भारत के सबसे अमीर बिज़नैस लीडर्स की संयुक्त संपत्ति में 30.5 अरब (2.63 लाख करोड़) डॉलर की भारी गिरावट आई है। संपत्ति में यह भारी गिरावट, भारतीय शेयर बाज़ारों में तेज़ गिरावट के बीच आई है, जिसकी शुरुआत हुई विदेशी निवेशकों द्वारा अपना पैसा बाज़ार से निकालने के कारण। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर ट्रेड को लेकर बढ़ता

- टॉप अरबपतियों की ''वैल्थ'' को 30.5 बिलियन डॉलर यानी 2.63 लाख करोड़ रूपये का झटका लगा है।
- सबसे बड़ा झटका हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड (एचसीएल) के मालिक व संस्थापक शिव नाडर को लगा, जिनकी वैल्थ 10.5 बिलियन डॉलर गिरी। यह सच है कि ग्लोबल स्लोडाउन में सबसे बड़ा झटका आईटी सैक्टर को लगा है, पर, शिव नाडर को हुए नुकसान से तो लगता है, इस अनिश्चितता की सारी मार शिव नाडर की कम्पनियों पर आई है।
- मुकेश अंबानी की सम्पदा पर भी 3.42 डॉलर की मार आई, एशिया में सबसे अमीर मुकेश अंबानी, जो विश्व के सबसे अमीरों की लिस्ट में ऊपर रहते आए हैं, पर, अब वे लुढ़क कर विश्व के सबसे समृद्धों की सूची में 17वें नम्बर पर आ गये हैं। उनकी फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इण्डस्ट्रीज़ को इतना भारी नुकसान नहीं हुआ, पर, उनकी दूसरी बड़ी कंपनी जियो फायनैंशियल सर्विसेज़ की ''वैल्यू'' 24 प्रतिशत घटी।
- अडानी ग्रुप की कंपनियों की ''नैटवर्थ'' 6.05 बिलियन डॉलर की कमी आई तथा अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एन्टरप्राइजेज की वैल्यू 9 प्रतिशत घटी।
- जिंदल ग्रुप की मुखिया, सावित्री जिंदल को भी झटका लगा, उनकी कंपनी की वैल्यू में 2.4 बिलियन डॉलर का नुकसान आंका जा रहा है।
- सन फार्मा के मालिक दिलीप संघवी ने भी वर्तमान इकोनॉमिक उथल-पुथल में 3.4 बिलियन डॉलर खोये।
- नुकसान साधारण इन्वेस्टर को भी हुआ है तथा सैंसैक्स व निफ्टी में 4.5 प्रतिशत की टूट आयी है, विशेषकर मध्यम श्रेणी व लघु श्रेणी की कंपनियों में 14 प्रतिशत व 17 प्रतिशत टूट हुई शेयर की कीमतों में।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## राज्य सरकार मैडिकल कॉलेजों के रिक्त पद भरने की योजना बनाये

जयपुर, 14 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पड़े पदों को भरने की क्या कार्य योजना है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि यदि किसी प्रकरण में अदालत की ओर से नियुक्ति पर रोक है तो उसकी अलग से स्पष्ट जानकारी दी जाए। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश महेन्द्र गौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा

- हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित में है कि मैडिकल कॉलेजों के सभी संकाय भरे जाएं।

कि यह वास्तव में जनहित में है कि मेडिकल कॉलेजों में सभी संकाय भरे जाएं और शिक्षण कर्मचारियों की कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में बताया गया कि प्रदेश में संचालित निजी मेडिकल कॉलेजों में खाली पद लगभग शून्य हैं। वहीं, राज्य सरकार और स्वायत्तशासी संस्थाओं की ओर से संचालित मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्टालिन उत्साहितः वाइस चांसलरों की मीटिंग बुलाई

### मीटिंग के मार्फत स्टालिन अब उन निर्णयों को उखाड़ना शुरु करेंगे, जो राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के चांसलर की हैसियत से लिये थे

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। राज्यपाल से चली लम्बी लड़ाई के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को अब उनसे बहला लेने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को हुए नुकसान की भरपाई करने का अवसर मिल गया है। इन संस्थाओं का राज्यपाल ने कुलाधिपति की हैसियत से भगवाकरण किया था।

मुख्यमंत्री ने उस नुकसान की भरपाई की शुरुआत करते हुये, बुधवार को सभी विश्वविद्यालयों के सभी उपकुलपतियों तथा रजिस्ट्रारों की एक मीटिंग राज्य सचिवालय में बुलाई है। अब इस अधिकार से वंचित हो जाने के बाद, राज्यपाल ठाले-बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते।

स्टालिन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के चान्सलर होने की हैसियत से, राज्यपाल का लक्ष्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के की प्रतिष्ठा को चूर-चूर कर देना था तथा उन्होंने उच्च शिक्षा का भगवाकरण करके अनैतिकतापूर्ण राजनीति स्थापित कर दी थी। स्टालिन ने इसके विरूद्ध विधानसभा में विधेयक पारित कराये थे। आशा की जा रही है कि परामर्श के लिये बुधवार को होने वाली इस मीटिंग में, उच्च शिक्षण संस्थानों को भगवाकरण से मुक्त करने की प्रक्रिया की नींव रख दी जायेगी तथा राज्यपाल के आदेश पर हुई नियुक्तियों को रद्द किये जाने की संभावनाएं हैं।

सोमवार को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुधवार की मीटिंग का एजेंडा राज्य की उच्च शिक्षा में सुधार करने के विषय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे कि विश्वविद्यालयों से संबंधित विभिन्न विधेयक, जो विधानसभा ने दोबारा भेजे हैं तथा राष्ट्रपति के पास लम्बित हैं, राष्ट्रपति की सहमति-प्राप्त माने जायेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के

- स्टालिन के अनुसार, वे तमिलनाडु के विश्वविद्यालयों का भगवाकरण खत्म करेंगे, जो राज्यपाल आर.एन. रवि, ने विश्वविद्यालयों के चांसलर की भूमिका में शुरु कर रखा था।
- उदाहरण के लिये, राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्तियां की थीं।
- राज्यपाल आर.एन. रवि ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भारी जोर दिया था तथा नई नीति को क्रांतिकारी व बदलाव लाने वाली नीति बताया करते थे। पर, अब तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी गठित की है,जो प्रदेश की शिक्षा नीति का नया ड्राफ्ट तैयार करेगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## रामविलास पासवान के भाई व केन्द्रीय मंत्री रहे पारस ने एनडीए से नाता तोड़ा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। इस वर्ष के अन्त में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य में राजनैतिक समीकरणों में भारी उलटफेर होना शुरु हो गया है। इसकी शुरुआत करते हुये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए छोड़ दिया है।

स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री पारस ने अंबेडकर जयन्ती पर एनडीए को छोड़ने की विधिवत घोषणा कर दी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केन्द्रीय नेताओं पर प्रहार करते हुये, उन्हें ''दलित-विरोधी'' बताया है।

उन्होंने संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने के मामले में गृहमंत्री अमित शाह का नाम लिया, साथ ही यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ''दलित - केन्द्रित पार्टी'' होने के नाते, आरएलजेपी की उपेक्षा की तथा उसका अपमान किया।

भाजपा द्वारा एलजेपी के पारस गुट के मुकाबले, पासवान के बेटे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट को खड़ा करने के कारण, पारस का एनडीए से सम्बंध विच्छेद अपेक्षित ही था।

जहाँ एलजेपी के संस्थापक राम विलास पासवान की मृत्यु के बाद, भाजपा पारस गुट के पक्ष में थी तथा उसने पारस को केन्द्रीय मंत्री तक बना दिया था, वहीं, लोकसभा चुनावों से पहले स्थितियाँ पूरी तरह उलट गईं तथा भाजपा ने चिराग गुट को अपने साथ ले लिया, तथा पारस के साथ सीट-शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया, जबकि आरएलजेपी के 17 वीं लोकसभा में 5 सांसद थे। पारस ने कहा, ''हमने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन एनडीए ने हमारा परित्याग कर दिया। उस समय यह स्पष्ट हुआ कि हमारी उपेक्षा दलित-केन्द्रित पार्टी होने के कारण की जा रही है।'' पारस ने आगे कहा, ''संभवतः भाजपा दलित-विरोधी है।

पारस ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद, उन्हें गठबंधन नेताओं की प्रमुख मीटिंगों से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा, ''भाजपा और जेडीयू का मानना है कि बिहार में एनडीए के केवल 5 घटक दल हैं। एनडीए के घटक दल के रुप में मेरी पार्टी का नाम भी नहीं लिया गया।''

हालाँकि पारस ने अपनी भविष्य की योजना नहीं बताई, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं कि उनका रुख

- पारस ने कहा कि उनकी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की लगातार अवहेलना हो रही है तथा उन्होंने मु.मंत्री नीतीश कुमार व केन्द्रीय नेताओं पर ''दलित विरोधी'' होने का आरोप भी लगाया।
- जब से भाजपा रामविलास पासवान के पुत्र चिराग को ज्यादा भाव दे रही थी, यह संभावना प्रबल हो गई थी कि पारस अब एनडीए छोड़ेंगे। अब संभवतया पारस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से जुड़ेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## हाई कोर्ट के दखल पर सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति मिली

जयपुर, 14 अप्रैल। सफाई कर्मचारी-2018 में नियुक्ति से वंचित किए गए अभ्यर्थियों को राजस्थान हाईकोर्ट के दखल के बाद राहत मिली है। अदालत में याचिका दायर होने के बाद दिए निर्देश को लेकर विभाग ने याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति मिलने पर अदालत ने मामले में दायर याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश हेमराज मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को सफाई कर्मचारी

- अतिरिक्त महाधिवक्ता गिल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के कार्यग्रहण के आदेश जारी हो चुके हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## चीन ने अमेरिका पर पलटवार किया

### अमेरिका को ''रेअर अर्थ'' खनिज व कैमिकल्स की सप्लाई भेजना स्थगित किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। अमेरिका व चीन के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि बीजिंग ने वॉशिंगटन को मर्मस्थल पर करारी चोट दी है, चीन ने बहुत सारे बेहद महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात रोक दिया है। ये तत्व कई आधुनिक हथियारों, इलैक्ट्रॉनिक्स वाहनों और विमानों और सेमीकंडक्टर कम्पनियों के लिए बेहद जरुरी हैं। इसके अलावा, कई उपभोक्ता वस्तुओं में भी इनका प्रयोग होता है।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक न्यूज़ रिपोर्ट कहती है कि चीन की सरकार निर्यात के लिए नया नियामक तंत्र विकसित कर रही है और चूंकि नीतियां बन रही हैं, इसलिए चुंबक के कई शिपमैंट्स चीन के बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। चुंबक कार से लेकर मिसाइल तक हर चीज बनाने में प्रयुक्त होता है। एक बार नया नियामक तंत्र अस्तित्व में आ गया तो यह कुछ कम्पनियों को दुर्लभ खनिजों की सप्लाई स्थाई रुप से रोक देगा। इनमें अमेरिका मिलिटरी कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल है, जिससे अमेरिका मिलिटरी -इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स पंगु हो जाएगा।

निर्यात पर रोक लगाना ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन का जवाब है। चीन के इस कदम का लक्ष्य अमेरिका की कमज़ोरी पर वार करना है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व पर चीन का एकाधिकार सा है। विश्व के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का लगभग 90 प्रतिशत चीन के पास है। रक्षा, इलैक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और इलैक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाले 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व चीन में ही मिलते हैं।

सात श्रेणी के मध्यम एवं भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों -सैमेरियम गैडोलिनीयम, टरवियम, डाइस्प्रोसियन, लुटेरियम, स्कैंडियम और यट्रियम को निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया गया। अमेरिका पास दुर्लभ पृथ्वी तत्व की मात्र एक खान है और दुर्लभ खनिज की अधिकांश आपूर्ति यह चीन से करता है।

बीजिंग ने 2 अप्रैल को पृथ्वी तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जो कि चीन पर टैरिफ बढ़ाने के ट्रंप के निर्णय के जवाब में उठाया गया चीन का कदम था। ट्रंप ने चीन के सामान पर तब 54 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, न केवल खनिजों, बल्कि चुंबक और अन्य तैयार सामान के निर्यात पर जो नियंत्रण लगाया गया है, उसे बदलना काफी मुश्किल है।

बीजिंग लम्बे समय से इसका संकेत दे रहा था और इस कदम से अमेरिका व चीन में तनाव और बढ़ सकता है और अमेरिकन कम्पनियां, जो दशकों से अपने उत्पादन के लिए इन तत्वों पर निर्भर हैं, वे भारी संकट में पड़ सकती हैं।

इन खनिजों और विशेष चुंबकों को विशेष निर्यात लाइसैंस के बाद ही बाहर भेजा जा सकेगा।

- ''रेअर अर्थ'' 17 खनिजों का समूह है, जो रक्षा, इलैक्ट्रिक वाहन, एनर्जी व इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्री में अति महत्वपूर्ण है और इनका कोई विकल्प नहीं है।
- चीन इन ''रेअर अर्थ'' मिनरल्स को निर्यात करने के लिये ''रेग्युलेटरी व्यवस्था'' विकसित कर रहा है। निर्यात करने के लिये लायसैंस जारी करेगा तथा बाद में इन मिनरल्स के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिये, कभी लायसैंस जारी करने कमी करके अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से संबंध उद्योगों, नई टैक्नोलॉजी, जैसे इलैक्ट्रिक कार, आदि प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी कंपनियों का गला घोंट सकेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## मेहुल चोकसी बेल्जियम में गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के हवाले से मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 65 वर्षीय चोकसी को शनिवार को हिरासत में लिया गया था और अभी वह बेल्जियम की जेल में है। सीबीआई ने चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था।

भारत की बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि है, हालांकि चोकसी द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग करने की उम्मीद है। चोकसी और उसके

- भारत की बेल्जियम से प्रत्यर्पण संधि है इसलिए सरकार चोकसी के प्रत्यर्पण की कवायद में जुटी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## सीमांत शहर मुर्शिदाबाद की हिंसा ने कोलकाता को भी अब चारों तरफ से घेर लिया

### भानगर, मिनाखान और बदनाम संदेश खाली में भी हिंसा व पुलिस वाहनों व सरकारी सम्पत्ति में आग लगाने का हिंसक क्रम पहुँचा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। प. बंगाल में मुसलमानों का हिंसक प्रदर्शन तेजी से फैल रहा है और कोलकाता के करीब पहुंच गया। गत सप्ताह सीमावर्ती जिले मुर्शिदाबाद में ही हिंसक प्रदर्शन था, पर मंगलवार को हिंसा व आगजनी कोलकाता के समीपवर्ती साउथ 24 परगना तक पहुंच चुकी थी।

गत सप्ताह के हिंसक हमले के पीछे संदेह है कि सीमा पार के जेहादी तत्वों ने हिंसा भड़काई थी। सोमवार को जो विरोध प्रदर्शन हुआ, वह नौशाद सिद्दीकी के संगठन आईएसएफ ने भड़काया था। यह व्यक्ति खुद को बंगाल में एक राजनैतिक ताकत के रुप में स्थापित करना चाहता है। पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई, घरों व दुकानों को लूटा गया। हिंसा फैलने के कारण मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से हिंदू पलायन कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति और उससे पहले वामपंथी दलों के 35 साल के कुशासन व तुष्टिकरण ने बंगाल को बारुद का ढेर बना दिया है। दोनों ने ही राज्य में सीमा पार से घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य का डैमोग्राफिक संतुलन बिगड़ गया है।

बंगाल में विभाजन से पहले के दिन लौट रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाके में हिंसा बढ़ रही है। अब पूरे राज्य में हिंसा फैल रही है।

विडम्बना यह है कि राज्य विधानसभा का एक मात्र मुस्लिम विधायक, जो अभी कोलकाता का मेयर है, उसने हिंसा को कमतर करके आंका और कहा कि हिंदू दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, राज्य नहीं छोड़ रहे हैं।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी ने राज्य में तुरंत केन्द्रीय बल तैनात करने की मांग की है, क्योंकि हिंसा रोकने में राज्य पुलिस पूरी तरह से विफल रही है।

मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के सर्वाधिक एक्टिव नेता की राशन की दुकान लूट ली गई। यह व्यक्ति तृणमूल से सम्बंधित संगठन राशन शॉप ओनर्स एसोसिएशन का

- पहले वामपंथियों द्वारा और अब तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित मुस्लिम मतदाता के तुष्टीकरण की नीति, अब अपना विकराल रूप दिखा रही है। दोनों पार्टियों ने बाँग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा दिया, अपने शासनकाल में, जिससे उनका वोट बैंक बढ़े।
- देश के बँटवारे के समय के दंगों की याद ताज़ा हुई, हिंदू जनसंख्या, घर छोड़-छोड़ कर पलायन कर रही है, किसी अन्य सुरक्षित स्थानों पर, मुख्यतया स्कूल बिल्डिंग्स में।
- एक तृणमूल नेता ने बेहूदी टिप्पणी की, कि हिंदू, बंगाल में अन्यत्र जा रहे हैं, बंगाल छोड़कर नहीं जा रहे।
- पहले दिन मुर्शिदाबाद में हुए दंगों को बाँग्लादेश से आये जिहादी तत्वों की करतूत बताया जा रहा था, पर, अब बंगाल में अन्यत्र, जैसे दक्षिण 24 परगना जिले में हिंसा फैलने से, यह बहाना नहीं दोहराया जा रहा, क्योंकि, साफ दिख रहा है, हिंसा के पीछे कौन लोग हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## राम मंदिर के शिखर पर कलश स्थापना

अयोध्या, 14 अप्रैल। अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर में सोमवार को ब्राह्मणों की उपस्थिति में वैदिक विधि-विधान के साथ मुख्य शिखर पर कलश स्थापित किया गया। यह पवित्र कार्य सुबह 9:15 बजे शुरू हुआ और 10:30 बजे शिखर पर कलश की स्थापना पूरी हुई। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि वैशाखी और बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्य संपन्न हुआ। अब मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजदंड स्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। मंदिर निर्माण प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि

- सुबह सवा नौ बजे से 10.50 के बीच विधिविधान से कलश स्थापना की गई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)